मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया।

नैशनल कॉन्फ्रैंस से समझौते ने कांग्रेस पार्टी के देश विरोधी मंसूबे बेनकाब किए : भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस, जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और अराजकता की ओर धकेलकर दलितों के आरक्षण को छीनना चाहती है

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर 10 सवाल दागे और कहा, कांग्रेस राजस्थान के जवानों की शहादत का अपमान कर रही है, जिन्होंने कश्मीर में आतंकियों के साथ संघर्ष में जान का बलिदान दिया है।**
- **भजनलाल शर्मा ने पूछा, क्या कांग्रेस पार्टी नैशनल कॉन्फ्रैंस के, जम्मू-कश्मीर में अलग झंडे के वादे और धारा 370 की बहाली की मांग का समर्थन करती है।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि नैशनल कॉन्फ्रैंस ने दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने का वादा किया है।**
- **मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी, जम्मू-कश्मीर में नैशनल कॉन्फ्रैंस पार्टी की भेदभाव की नीति की पक्षधर है।**

जयपुर, 24 अगस्त (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रैंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और अराजकता की ओर धकेलकर दलितों के आरक्षण को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा, जिस जम्मू कश्मीर की शांति के लिए राजस्थान के युवाओं ने बलिदान दिया, उस राजस्थान के लोगों के मन में आज कांग्रेस के प्रति गहरी नाराज़गी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 (ए) को हटाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वहां अमन, समृद्धि और सुरक्षा की नई इबारत लिखी है, जिसे कांग्रेस, पाक पोषित परिवारवादी पार्टी से गठजोड़ कर देश के मणि मुकुट को फिर से अशांत करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने वहां के युवाओं को गुमराह कर उनके हाथ में एके-47 थमाने का काम किया, उन पार्टियों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। इससे कांग्रेस पार्टी के देश विरोधी मंसूबे बेनकाब हुए हैं।

इस अवसर पर मंच पर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल कांफ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर 10 सवाल दागे:

1) क्या कांग्रेस "नेशनल कांफ्रेंस" के जम्मू-कश्मीर में फिर से "अलग झंडे" के वादे का समर्थन करती है?

2) क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के "नेशनल कांफ्रेंस" के निर्णय का समर्थन करती है?

3) क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?

4) क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, पाकिस्तान के साथ "एलओसी ट्रेड" शुरू करने के नेशनल कांफ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं?

5) क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है?

6) इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के "नेशनल कांफ्रेंस" के वादे के साथ है?

7) क्या कांग्रेस चाहती है कि "शंकराचार्य पर्वत" तख़्त-ए-सुलिमान और "हरि पर्वत" कोह-ए-मारन के नाम से जाने जाएं?

8) क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौपने का समर्थन करती है?

9) क्या कांग्रेस पार्टी "नेशनल कांफ्रेंस" के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?

10) क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की "नेशनल कांफ्रेंस" की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं?

पुणे में हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 4 घायल

पुणे, 24 अगस्त। महाराष्ट्र के पुणे शहर के पौड गांव में गरवा होटल के पास शनिवार को एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोग घायल हो गये।

- **हैलीकॉप्टर निजी कम्पनी का था। बताया जाता है कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है।**

पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर उडान भरने के कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस समय यह घटना घटी हेलीकॉप्टर में चार लोग सवार थे, जो घायल हो गये , हालांकि किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान में मदद की।

ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष ने बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार हेलीकॉप्टर एक निजी विमानन कंपनी का है और मुंबई से हैदराबाद जा रहा था।

प्रज्वल रैवन्ना के खिलाफ एस.आई.टी. ने दो हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

इस चार्जशीट में तकरीबन 150 गवाहों के बयान दर्ज हैं। एस.आई.टी. ने प्रज्वल रैवन्ना और उनके पिता एच.डी. रैवन्ना को चार्जशीट में आरोपी बनाया है

- **प्रज्वल रैवन्ना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा के पौत्र हैं। प्रज्वल पर घरेलू नौकरानी के यौन शोषण का आरोप है।**
- **ज्ञातव्य है कि, लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें प्रज्वल को अनेकों महिलाओं का यौन शोषण करते हुए दिखाया गया था। वीडियो सामने आने के बाद प्रज्वल विदेश भाग गया था, बाद में जब वह लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।**

नई दिल्ली, 24 अगस्त। अपराध जांच विभाग के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म मामले और उनके पिता एवं विधायक एच डी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रज्वल के खिलाफ चार मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने कहा कि 2,000 से अधिक पृष्ठों के आरोप पत्र में करीब 150 गवाहों के बयान दर्ज हैं। एक विशेष अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसमें रेवन्ना परिवार की एक घरेलू सहायिका के कथित यौन शोषण से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। आरोप पत्र में घटनास्थल का निरीक्षण, जैविक, भौतिक, वैज्ञानिक, मोबाइल, डिजिटल तथा अन्य प्रासंगिक साक्ष्य शामिल हैं।

एसआईटी ने बताया कि, आरोप पत्र दाखिल किए जाने से पहले विशेषज्ञ की राय भी ली गयी है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्यूलर) प्रमुख एच डी देवेगौड़ा के बेटे एवं विधायक रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 (ए) के तहत आरोप लगाए गए हैं, जबकि, उनके 33 वर्षीय बेटे प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 (2) (के), 354, 354 (ए) और 354 (बी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पिता-पुत्र के खिलाफ पहली शिकायत उनके आवास पर घरेलू सहायिका रही महिला ने दर्ज कराई थी। पीड़िता विधायक की पत्नी भवानी की रिश्तेदार भी है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया गया।

ज्ञातव्य है कि प्रज्वल ने हासन सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार के तौर पर हाल में लोकसभा चुनाव लड़ा था और वह हार गया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सोशल मीडिया पर कई अश्लील वीडियो सामने आए जिसमें प्रज्वल द्वारा कई महिलाओं का यौन शोषण करते हुए देखा गया।

नीतिश कुमार ने जद (यू) में भारी फेरबदल किया

- **पुरानी प्रदेश कमेटी भंग कर नई कमेटी बनाई, 150 नेताओं को बाहर किया**
- **नीतिश कुमार ने 23 मार्च 2023 को प्रदेश कमेटी का गठन किया था, जिसमें 251 पदाधिकारियों को शामिल किया गया था।**

पटना, 24 अगस्त। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां पार्टी ने आज सुबह-सुबह अपनी प्रदेश कमेटी और राजनैतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद नई प्रदेश कमेटी का ऐलान भी कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में जेडीयू ने अपनी प्रदेश कमेटी से करीब 150 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

ज्ञातव्य है कि, 23 मार्च 2023 को जेडीयू की प्रदेश कमेटी का गठन हुआ था। उस समय पार्टी ने 251 पदाधिकारियों वाली प्रदेश कमेटी का एलान किया था, जिसमें 20 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव और 11 प्रवक्ता बनाये गये थे। कुल मिलाकर जेडीयू के करीब 260 प्रदेश पदाधिकारी की पूरी टीम थी। प्रदेश कमेटी का कार्यकाल अमूमन तीन साल का होता है, लेकिन 15 महीने में ही पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया।

अब नई कमेटी का ऐलान आज सुबह किया गया है। नई कमेटी का ऐलान होने के बाद पुरानी कमेटी में से ज्यादातर नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। पार्टी की नई प्रदेश कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 प्रदेश महासचिव, 46 प्रदेश सचिव, 9 प्रवक्ता और एक कोषाध्यक्ष बनाये गये हैं। पार्टी ने 260 पदाधिकारियों वाली पुरानी टीम में से करीब 75 नेताओं को ही नई कमेटी में जगह दी है।

जेडीयू की पुरानी प्रदेश कमेटी में पूर्व मंत्री रंजू गीता, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, श्याम बिहारी प्रसाद, पूर्व विधायक अशोक कुमार, मुजाहिद आलम, लखन ठाकुर, लक्ष्मेश्वर राय, जय कुमार सिंह, खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम समेत 20 नेताओं को उपाध्यक्ष का पद मिला था। इन तमाम नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। वहीं, प्रदेश उपाध्यक्षों की नई सूची में पूर्व सांसद महाबली सिंह, पूर्व एमएलसी हारून रशीद, एमएलसी संजय सिंह, प्रमिला कुमार प्रजापति, अमर कुमार अग्रवाल, वैद्यनाथ सिंह विकल, कलाधर मंडल, एमएलसी रविंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी और अजीत चौधरी का नाम शामिल है।

चिकित्सा विभाग के अफसरों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किए गए नर्सिंग ऑफिसर के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उस पर काउंटर साइन नहीं किए और अनुभव प्रमाणपत्र को सत्यापित नहीं किया। इसकी वजह से याचिकाकर्ता को भर्ती की अस्थायी चयन सूची में शामिल नहीं किया गया।

अभयर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। याचिका को गत दिसंबर माह में हाईकोर्ट ने निस्तारित करते हुए विभाग को निर्देश दिए थे कि वह 9 नवंबर, 2023 को अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में बनाई पॉलिसी के आधार पर याचिकाकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे। याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश की पालना के लिए विभाग में कई बार अभ्यावेदन भी पेश किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में बताया गया कि पूर्व में विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सभी सी.एम.एच.ओ. को सामान्य निर्देश जारी किए, लेकिन याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया गया।

याचिका में यह भी कहा गया कि गत 12 जुलाई को विभाग ने विभिन्न योजनाओं में कार्यरत रहने के दौरान जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने के लिए एक फॉर्मेट जारी किया गया। इसके तहत अन्य कर्मचारियों के प्रमाण पत्र सत्यापन किए गए, लेकिन याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया गया। अवमानना याचिका में गुहार की गई कि अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों को दंडित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अमेरिका के फैडरल रिज़र्व बैंक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर सकने वाले कारकों में हैं मंहगाई और कीमतों में आगे आने वाला संभावित उछाल। कीमतें पिछले कुछ महीनों से संयमित रही हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा गत सप्ताह जारी की गई नवीनतम मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कीमतों को लेकर एक सुखद तस्वीर पेश की गई थी। कुलमिलाकर, वर्ष 2024 के वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों-अप्रैल से जुलाई के बीच खुदरा मंहगाई दर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 5.3 प्रतिशत की तुलना में 4.6 प्रतिशत रही।

कंजूमर प्राइस इन्डैक्स-कम्बाइन्ड (सी.पी.आई.सी.) पर आधारित खुदरा मंहगाई दर जो जून 2024 में 5.1 प्रतिशत थी, जुलाई 2024 में घटकर 3.5 प्रतिशत तक आ गई। यह आंकड़ा सितम्बर 2019 से अब तक न्यूनतम है। वित्त मंत्रालय ने इसका कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई में महत्वपूर्ण कमी आना माना है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर, जो जून 2024 में 9.4 प्रतिशत थी, वह जुलाई 2024 में कम होकर 5.4 प्रतिशत हो गई। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में जो महत्वपूर्ण कमी देखने को मिली उसका प्रमुख कारण फल-सब्जियों की मंहगाई दर में कमी आना था। इनकी महंगाई दर जून 2024 में जहां 29.3 प्रतिशत थी, वहीं यह जुलाई 2024 में बहुत घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई। यद्यपि यह आंकड़ा बाजार की छिपी हुई मंहगाई दरों के बिलकुल विपरीत है, खासतौर पर फल-सब्जियों की कीमतों के मामले में।

अब प्रश्न ये है कि क्या कीमतों का संयमित होना अस्थायी है अथवा यह एक दीर्घ ट्रैण्ड का सूचक है। यदि महंगाई दर में अचानक से आई यह कमी कुछ ही समय बाद अपने पिछले स्तर पर आ जाती है तो फिर आर.बी.आई. को मंहगाई विरोधी रुख अपनाने से परहेज नहीं करना चाहिए, और यदि कीमते कम स्तरों पर ही बनी रहती है तो फिर आर.बी.आई. के पास अपनी नीतिगत ब्याज दरों को पुनर्व्यस्थित करने का मौका है, लेकिन फिलहाल तो यह मुश्किल प्रतीत होता है।

17 साल के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वीडियो वायरल कर दिया। जब इसकी जानकारी पीड़ित के पिता को मिली तो उसने 18 जुलाई, 2020 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने बाल न्यायालय में तीस अक्टूबर, 2020 को तीनों नाबालिगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। वहीं किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को मानसिक रूप से परिपक्व और सोचने समझने में सक्षम मानते हुए प्रकरण को सामान्य मुकदमे के तौर पर सुनवाई के लिए डी.जे. कोर्ट में भेज दिया था। जहां से मामला पॉक्सो कोर्ट में भेजा गया। जहां किशोर के खिलाफ अन्य आपराधिक मुकदमों की तरह ट्रायल चलाया गया।

'हरियाणा में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा राज्य में चुनाव प्रक्रिया पांच सितंबर से शुरू होगी, मतदान एक अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती चार अक्टूबर को होगी। उन्होंने चुनाव आयुक्त को ध्यान दिलाते हुये लिखा कि मतदान के दिन से पहले दो राजपत्रित छुट्टियां हैं, यानी 28 सितंबर को शनिवार और 29 सितंबर को रविवार है।

एक अक्टूबर को भी मतदान अवकाश है और उसके बाद दो राजपत्रित छुट्टियां होंगी। यानी दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और तीन अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है। चूंकि लोग आमतौर पर लंबे सप्ताहांत पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा।

मत प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा चुनाव के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ चुनाव की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष औसत वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन मिलेगी

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।**

नयी दिल्ली, 23 अगस्त। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नयी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।

यूपीएस के लिये सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान करेगी और इसमें फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान के भी प्रावधान किये गये हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुये सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, यह योजना पूर्ण रूप से वित्तीय व्यवस्था के साथ लागू की जा रही है। यह कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की योजनाओं के तहत कोई खोखला वादा नहीं है। उन्होंने बताया कि इस योजना से 30 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14 प्रतिशत अंशदान करती है, इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिये होगा।

मुम्बई की 36 में से 20-22 सीटों पर दावा किया उद्धव ठाकरे ने

महाविकास अघाड़ी की बैठक में मुम्बई की 36 सीटों पर चर्चा हुई

- **मुम्बई में उद्धव ठाकरे की शिव सेना मजबूत है इसलिए एन.सी.पी. ने ठाकरे के दावे पर सहमति जताई।**
- **लेकिन कांग्रेस तकरीबन 15-18 सीटों पर दावा कर रही है, इसे देखते हुए सीटों के तालमेल की वार्ता में असहमति बन सकती है।**

मुंबई, 24 अगस्त। आज महाविकास आघाड़ी की बैठक में मुंबई की 36 सीटों पर शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्राथमिक रूप से यह चर्चा हुई कि यूबीटी शिवसेना मुंबई में मजबूत है तो वह ज्यादा सीटों पर लड़े। एनसीपी और यूबीटी इस बात पर सहमत हैं।

मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव शिवसेना क़रीबन 20 से 22 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस 15 से 18 सीट पर लड़ना चाहती है और एनसीपी शरद पवार 4 से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है। बैठक में उन सीटों पर भी चर्चा हुई, जो बीजेपी, एनसीपी अजित गुट, महायुति ने जीती हैं।

पिछले चुनाव में जो सीट जिस पार्टी ने जीती हैं, वह सीट उस पार्टी के पास कायम रहे यह शिवसेना की मांग है। 2019 में शिवसेना संयुक्त 14 सीटें जीती थी। अब उद्धव के पास 8, शिंदे के पास मुंबई में 6 विधायक हैं। इस दौरान कांग्रेस ने 4, एनसीपी ने एक और समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती थी।

बैठक के बाद एमवीए की तरफ से जितेंद्र आव्हाड़ ने बात की और कहा कि मुंबई में उद्धव शिवसेना की पकड़ मजबूत है इसलिए जाहिर है कि वह बड़े भाई की भूमिका में होंगे। एनसीपी शरद पवार कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह जब तय होगा तब सामने आएगा। आज की बैठक में भी एमवीए ने बदलापुर मामले पर ज्यादा चर्चा होने का हवाला दिया।

बैठक में कांग्रेस से मुंबई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, जगताप, असलम शेख शामिल हुए। वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना से संजय राउत, अनिल देसाई, एनसीपी से जितेंद्र आ ड और मुंबई एनसीपी अध्यक्ष जाधव उपस्थित रहीं। मुंबई में एमवीए में कुछ सीटों को एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे चांदीवाली सीट शिवसेना ने जीती थी। अब विधायक दिलीप लांडे शिंदे शिवसेना में हैं तो वह सीट नसीम ख़ान के लिये कांग्रेस को दी जाएगी।

कमला हैरिस की राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिता चिलकुरी राधाकृष्णन ने अमेरिका में पढ़ाई की थी तथा जे.डी.वैन्स के साथ शादी होने से पहले, उषा सेन डिएगो में बड़ी हुई थीं। डॉ. चक्रवर्ती ने राजनैतिक लाभ के लिये अपने सिद्धान्तों से कथित समझौते को लेकर वैन्स परिवार की आलोचना की तथा कहा कि इस परिवार ने सत्ता तक आसानी से पहुँचने के लिये कन्ज़रवेटिव मूल्यों के समझौता करने में अपने विचारों का समायोजन किया है।

डॉ. चक्रवर्ती ने हैरिस और ट्रम्प की नीतियों में विरोध को उजागर करते हुये कहा कि ट्रम्प का फोकस अबरपतियों के लिये 'टैक्स-बेक्स' पर तथा कॉर्पोरेट पॉल्यूटर्स के लिये डीरेगुलेशन पर है, जबकि हैरिस तेल और गैस उद्योग को जवाबदेह ठहराने के लिए कृतसंकल्प हैं। उनका जोर स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने तथा सभी अमेरिकनों के लिये 'क्लाइमेट एक्शन बेनिफट्स' सुनिश्चित करने पर है। जब हैरिस 2020 में उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थीं, उनका क्लाइमेट प्लान उससे ज्यादा हमलावर था, जो बाइडन के राष्ट्रपति काल में कुल मिलाकर पारित हो सका। इस दौर में 'इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट' बना था, जो निश्चित रूप से मिलेगा।" इससे पूर्व, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा सत्तारूढ़ दल के लिये सबसे बड़ा अभिशाप रहा है।

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार द्वारा बड़ी से बड़ी मात्रा में की जा रही लीपा-पोती इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि नौकरियों के लिये लाखों लोगों को सड़कों पर रोजाना संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें नगण्य रोजगार मिल पाते हैं। दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का भाजपा का जुमला हर भारतीय के साथ भाजपा के लज्जाहीन विश्वासघात को दर्शाता है।" उल्लेखनीय है कि कांग्रेस तथा इंडिया ब्लॉक के अन्य दल बेरोजगारी के मुद्दे के समाधान में कथित विफलता को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।

'बुलडोज़र कभी भी "नैचुरल जस्टिस" का विकल्प नहीं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उदयपुर के एम.बी. अस्पताल के आई.सी.यू. में उसका इलाज चला, लेकिन एकाएक उसकी हालत बिगड़ जाने पर 19 अगस्त को अपरान्ह करीब 4.40 बजे मृत्यु हो गई।

बताया जाता है कि हिन्दू-समूहों तथा भाजपा नेताओं ने बार-बार उत्तर प्रदेश शैली में बुलडोजर-कार्यवाही की माँग की तो उदयपुर जिला प्रशासन ने आरोपी परिवार के किराये के मकान को ढ़हा दिया। प्रशासन ने कहा कि मकान इसलिए गिराया गया क्योंकि मकान वन-भूमि पर गैर कानूनी तौर पर बना हुआ था।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यत: अल्पसंख्यकों की सम्पत्तियों पर बुलडोजर चला रही है तथा देश की अदालतें या तो न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के उल्लंघन की अनदेखी कर रही है या फिर ऐसे कारनामों की उपेक्षा कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ तो एक विशिष्ट भाषा-शैली में "बुलडोजर बाबा" कहे जाते हैं।

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कड़ा प्रहार किया था तथा कहा था कि सत्तारूढ़ दल की "युवा-विरोधी नीतियों के कारण, देश में रोजगारों का "अकाल" है।

खड़गे ने "एक्स" पर की गई एक पोस्ट में लिखा था, "मोदी सरकार की युवा-विरोधी नीतियों के कारण, देश में रोजगारों का अकाल पड़ गया है। हमारे लाखों युवा मुट्ठी भर नौकरियों के लिए भटक रहे हैं।" बिहार के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "बिहार में कॉन्स्टेबल भर्ती हो रही है जिसमें 21,000 खाली पदों के लिए 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।"

उत्तरप्रदेश का जिक्र करते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, " उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टेबलों के 60,000 पदों के लिए 6.30 लाख युवकों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा का प्रश्नपत्र एक बार लीक हो चुका है।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलते हुए, उन्होंने कहा, "मोदी जी को गलत तरीके से तैयार की गई एक रिपोर्ट मिल गई थी तथा उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के झूठे दावे कर दिये थे।" उन्होंने कहा, "के.एन.ई.एम.एस. के आँकड़ों से नकली विवरण तैयार करने के लिये, मोदी सरकार ने, जनगणना की मदद लेने के बजाय, अलग-अलग वर्षों के भिन्न-भिन्न जनसंख्या-आँकड़ों की मदद ले ली थी, जिसके कारण "कर्मचारी जनसंख्या अनुपात"(वर्कर पॉपुलेशन रेशियो) गलता था। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी आबादी की ग्रोथ को समान मान लिया गया था, जिसके चलते वस्तुस्थिति से ज्यादा अनुमान लगा लिये गये।"

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के आसन्न विधानसभा चुनावों के संदर्भ में खड़गे ने कहा, "भारत के हताश बेरोजगार युवा अब मोदी सरकार की इन चालबाजियों को समझ गये हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को इससे सबक सीखने का अवसर

सोपोर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हालांकि एक जवान भी घायल हो गया जिसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह अभियान समाप्त हो गया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908